जल शक्ति मंत्री व 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किसान परियोजना के एमओयू पर हस्ताक्षर किए

इस परियोजना से राजस्थान सहित 6 राज्यों की सिंचाई व पेयजल आवश्यकताओं की जलापूर्ति होगी- भजनलाल

नई दिल्ली/जयपुर, 15 सितंबर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को नई दिल्ली में किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के लिए एमओयू हुआ। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमालच प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया कि उनके विज़न से दशकों से अटकी परियोजनाओं का राज्यों की आपसी सहमति से समाधान हो रहा है।**

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंगलवार को छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समझौते को राज्यों के बीच आपसी सहयोग की मिसाल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने "सबका साथ-सबका विकास-सबका प्रयास-सबका विश्वास" के विजन को तेजी से आगे बढ़ाया है, जिससे राज्यों की सहमति से दशकों से अटकी परियोजनाओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से राजस्थान सहित, 6 राज्यों में सिंचाई, पेयजल सहित अन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त जलापूर्ति हो सकेगी। इससे प्रदेशों का निरंतर विकास होगा। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित, संबंधित राज्यों के मंत्रीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

भाजपा ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वहीं, रेजीनगर से मुर्शिदाबाद के पूर्व भाजपा अध्यक्ष और पार्टी की राज्य समिति के सदस्य शंकरभ सरकार को उम्मीदवार बनाया गया है।

चंद्रनाथ रथ की छह मई को उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय वह शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक थे।

चंद्रनाथ कार में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे थे, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उन पर और चालक पर गोलियां चला दीं। हमले में चालक भी घायल हुआ था। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया था।

शुरुआत में राज्य पुलिस ने मामले की जांच की थी और विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था। बाद में जांच का जिम्मा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया गया।

'निगमों, परिषदों और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विरूद्ध है, बल्कि निकायों के लिए बने अधिनियम के भी विरूद्ध है। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक साथ लॉटरी आयोजित करने से परिणाम यह हुआ है कि 10 नगर निगमों में से एक भी सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित नहीं है, 47 नगर परिषदों में केवल दो सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 252 नगरपालिकाओं में से 49 अनुसूचित जाति के लिए और 10 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 243 और राजस्थान नगरपालिका एक्ट, 2009 की धारा 5 के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं को जनसंख्या, जनसंख्या के घनत्व और राजस्व के उत्पादन की क्षमता तथा गैर कृषि रोजगार की उपलब्धता के मापदण्डों के अनुसार बांटा गया है। परंतु सभी 309 निकायों को एक ही तर्ज पर रखकर एक साथ लॉटरी आयोजित करने की प्रक्रिया को अपनाने के कारण स्वायत्तशासी विभाग ने असमान निकायों को एक समान बनाने का कार्य किया है। इस प्रक्रिया से जनांकिक और आर्थिक मापदण्डों को भी नगर अंदाज किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील यशोधर पांडे ने भी कहा कि हरियाणा व मध्यप्रदेश में निकायों के चुनाव आयोजित कराने से पूर्व नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों के लिए अलग-अलग लॉटरी आयोजित की जाती हैं, बोर्ड के अध्यक्ष की सीट आरक्षित करने से पूर्व। याचिकाकर्ता का कहना है कि अगर अलग-अलग लॉटरी आयोजित करायी जाती तो आरक्षित सीटों की गणना नहीं बढ़ती, परंतु यह सुनिश्चित किया जा सकता कि निकायों के हर स्तर पर अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर भी मिलता।

कलकत्ता ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पर सीआईडी पूछताछ के लिए आज़ाद को बुला सकती है। इसके लिए उन्हें कम से कम सात दिन पहले नोटिस देना होगा। आरोप है कि पिछले वर्ष 21 मई को एक कारोबारी को दुर्गापुर स्थित कीर्ति आज़ाद के बंगले पर बुलाया गया था। आरोप के अनुसार, आज़ाद के एक सहयोगी ने कारोबारी से 15 लाख रुपये की मांग की थी। कारोबारी का दावा है कि रकम नहीं देने पर उसका कुकिंग गैस का कारोबार बंद कराने की धमकी दी गई थी। उसने यह भी दावा किया कि पूरी घटना की ऑडियो रिकॉर्डिंग उसके पास है।

चीन व अमेरिका के बीच शीत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जब अमेरिकी टैक्नॉलजी इण्डस्ट्री के दिग्गज इस नए प्लेटफॉर्म की संभावित विनाशकारी शक्तियों को उजागर कर रहे हैं, तो अमेरिका के नेता डॉनल्ड ट्रंप इन बातों को केवल डर फैलाने वाला प्रचार कहकर खारिज कर रहे हैं। वे इस बात पर अड़े हैं कि अमेरिकी उद्योग को बिना रुके आगे बढ़ना चाहिए और चीनी कंपनियों पर बढ़त हासिल करनी चाहिए।

यह केवल एक दौड़ जीतने की बात नहीं है, बल्कि दुनिया की शीर्ष शक्ति के रूप में अमेरिका के अस्तित्व का सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा है कि उद्योग के नेताओं की सलाह मानकर एआई उद्योग की प्रगति पर कोई भी रोक लगाना चीन को बिना किसी मुकाबले के यह दौड़ जीतने का मौका देने जैसा होगा।

दूसरी ओर, चीन अमेरिका की बराबरी करने और उससे आगे निकलने के लिए तेजी से कोशिश कर रहा है। चीन ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहले ही एक विस्तृत योजना तैयार कर ली है और भारी मात्रा में धन तथा संसाधन जुटाए हैं। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तैयार किए गए व्यापक कार्यक्रमों के जरिए चीन इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए गहन प्रयास कर रहा है।

एआई क्षमताओं के मामले में चीन अब लगभग अमेरिका के बराबर पहुंच चुका है और वह किसी भी कीमत पर इस लक्ष्य तक पहुंचकर अमेरिका पर स्पष्ट बढ़त हासिल करना चाहता है। यहाँ तक कि शी जिनपिंग भी इस प्रयास से सीधे जुड़े हुए हैं और चीन को स्पष्ट बढ़त दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह टकराव हमारी दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच का टकराव बन चुका है। इनके बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा का बाकी दुनिया पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

अब एयर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुशंसित उम्मीदवारों में उनका शामिल होना उनकी भागीदारी, मूल्यांकन और योग्यता आधारित चयन का दस्तावेजी सबूत है।

ट्रस्ट ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी और दस्तावेजों में दर्ज की गई थी तथा संस्थागत काम-काज के उच्चतम मानकों के अनुसार आयोजित की गई थी। केन्द्र या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पांडे की पॉडकास्ट टिप्पणियों पर कोई अलग और विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि, मिश्रा ने इस भूमिका के लिए अपनी उपयुक्तता का बचाव करते हुए, वायुसेना के ठिकानों पर मंदिरों की देखरेख करने के अपने पूर्व अनुभव पर जोर दिया और मंदिर प्रशासन को प्रचार का नहीं, बल्कि कर्तव्य का विषय बताया।

'जल्द ही ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दूरी कम करने में मदद मिल सकती है, जो जटिल कानूनी शब्दावली को समझने में सहज नहीं हैं।

कोर्ट ने कहा कि इस पहल को चरणबद्ध तरीके से अन्य भारतीय भाषाओं में विस्तार देने से अलग-अलग भाषाई क्षेत्रों के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में संक्षिप्त और आसानी से समझ आने वाली जानकारी अपनी भाषा में मिल सकेगी।

पाकिस्तान पीछे हटा, सऊदी अरब ने इज़राइल से मदद मांगी

तेल अवीव, 15 सितंबर। सऊदी अरब के सामने यमन में हूती लड़ाकों के बढ़ ते प्रभाव के बीच बड़ा सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। लाल सागर के तट और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बड़े हिस्से पर हूतियों के कब्जे के बाद सऊदी अरब अपने ही सहयोगियों से अपेक्षित सैन्य मदद नहीं जुटा पा रहा है। खास तौर पर मक्का रक्षा समझौते के साझेदार पाकिस्तान और तुर्किये ने यमन में हूतियों के खिलाफ सैन्य अभियान में शामिल होने से दूरी बना ली है। ऐसे में सऊदी अरब ने अमेरिका की सेंट्रल कमांड के जरिए इज़रायल से खुफिया मदद मांगने का रास्ता अपनाया है।

यह घटनाक्रम सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किये के बीच हुए मक्का रक्षा समझौते पर गंभीर सवाल खड़े करता है। समझौते में एक साझेदार पर सैन्य हमला पूरे गठबंधन पर हमला माने जाने और उसके खिलाफ मिलकर जवाब देने की बात कही गई थी। इसके बावजूद हूती हमलों और यमन में बदलते हालात के बीच पाकिस्तान और तुर्किये की सैन्य भागीदारी नजर नहीं आ रही है। वहीं, सऊदी अरब को ऐसे देश से अप्रत्यक्ष मदद मांगनी पड़ रही है, जिसे वह स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता तक नहीं देता है।

- **हूती हमलों के बीच सऊदी अरब, तुर्किये व पाकिस्तान का मक्का रक्षा समझौता विफल हुआ**

सऊदी अरब के सामने यमन में हूती लड़ाकों के बढ़ ते प्रभाव के कारण गंभीर सुरक्षा और ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है। हूतियों ने पिछले सप्ताह लाल सागर के तट और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही जलडमरूमध्य के महत्वपूर्ण द्वीपों पर भी उनका नियंत्रण हो गया है।

हूती नेताओं ने कहा है कि जुलाई से लागू सऊदी जहाजों की नाकाबंदी जारी रहेगी, जबकि अमेरिका और दूसरे देशों के जहाजों को जलडमरूमध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने की अनुमति होगी।

गुरुग्राम हिट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चाहिए था कि मुझे कहीं चोट तो नहीं लगी।" उन्होंने आगे कहा कि इस दुर्घटना के परिणाम इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते थे।

ईडी के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

241 की जाएगी। इस व्यवस्था को 01 जनवरी 2027 से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। सम्मेलन में ईडी निदेशक ने अधिकारियों को आर्थिक अपराधों, बैंक धोखाधड़ी, बिल्डर-खरीदार धोखाधड़ी, दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) से जुड़े मामलों और साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और मुकदमों में दोषसिद्धि बढ़ ाने पर जोर दिया।

सुप्रीम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लॉन्ड्रिंग का नहीं बनता। जवाब में ईडी ने कहा कि आरोपी की ओर से गवाहों को प्रभावित करने और सबूत नष्ट करने का प्रयास हो रहा है।

वहीं, ईडी ने जयपुर जेल में यादव के पास से कथित तौर पर मोबाइल फोन बरामद होने के बाद नई एफआईआर दर्ज होने की बात भी अदालत को बताई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908